**Houses of Directors of F.C.I. Raided by C.B.I.**

*307. SHRI MD. JAMILUURAHMAN:
SHRI R. P. YADAV:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether the CBI has raided houses of some Directors of the Fertilizer Corporation of India following complaints from Members of Parlia, ment and if so the names of Directors and dates and places of raids and the documents and money recovered;

(b) whether raids were not simultaneously held at New Delhi, Calcutta and Sindri residences; and

(c) the follow-up action proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI D. K. BOROOAH): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

**श्री मुहम्मद जमीलर्रहमान** : मोहतरम सदर, बार के टाइम में यह सुन रहे थे कि एलाइड फोर्सेज और एक्सेस फोर्सेस वगैरह वगैरह थे, लेकिन इस फर्टिलाइजर कारपोरेशन में ट्रायो फोर्सेज हैं और उन ट्रायो फोर्सेज ने इस ग्रीन रेवोल्यूशन को पीछे करने में कितना बाधा दिया है वह मैं कल बयान करूंगा जब कि काल अटेंशन पर मैं बहस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि मैनेजिंग डायरेक्टर फर्टिलाइजर के और डायरेक्टर आफ प्रोडक्शन के खिलाफ बहुत से सीरियस चार्जेज आफ करप्शन हैं और उन के बावजूद भी आप के विभाग में उस में से एक आदमी को चेयरमैन बनाया है? इस के अलावा जो एन्क्वायरी सी०बी०आई० की हो रही है उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है और सी० आई० रूल्स के मातहत उन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री देवकान्त बरुआ : सदस्य महोदय ने पूछा है कि कुछ इल्जामात इन लोगों के खिलाफ मेम्बर-पार्लियामेन्ट ने लिख कर भेजा था—उन के बारे जांच हो रही है। उस में एक शिकायत यह भी थी कि ट्राम्बे में 20 लाख रुपया सस्पेंस एकाउन्ट में जमा हुआ है। मैंने उस की जांच करने के लिए अपने एक ज्वाइन्ट सैक्रेटरी को भेजा था। उन्होंने बताया कि 20 लाख तो नहीं, लेकिन 13 लाख रुपया सस्पैंस एकाउन्ट में जमा है। मैंने तुरन्त सी०बी०आई० को इस मामले को सुपुर्द कर दिया और वहां के मार्केटिंग डायरेक्टर मुखर्जी साहब और जैनरल मैनेजर को छुट्टी पर जाने दिया। सी०बी०आई० इस के बारे में जांच कर रही है।

**श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : मोहतरिम सदर, बहुत ज्यादा तादाद में प्राइवेट ट्रेडर्स को फर्टिलाइजर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहाल किया गया है, एजूकेटेड अनएम्पलाएड के नाम पर बहाल किया गया है। क्या मिनिस्टर साहब इस बात की एन्क्वायरी करायेंगे कि एजूकेटेड अनएम्पलाएड के नाम से जितनी एजेन्सीज दी गई हैं, वे उन लोगों को दी गई हैं, जिन्होंने घुसपैठ की है या करप्शन के जरिये उन पर हावी हो गये हैं?

**श्री देव कान्त बरुआ** : यह जो 13 लाख रुपया सस्पेंस एकाउन्ट में जमा हुआ है, यह प्राइवेट ट्रेडर्स के साथ जो बिजनेस हुआ है, उसी का नतीजा है—इस की जांच की जायगी। मेम्बर साहब ने अभी एजूकेटेड अनएम्पलाएड यंगमैन के बारे में कहा है, उन के नाम से एजेन्सियां देने में कुछ शरारतें की गई हैं, उन के बारे में भी इस में जांच होगी और मैं इस के ऊपर खास तौर से तवज्जह दूंगा।

SHRI R. P. YADAV: In view of the fact that the condition of the Fertiliser Corporation of India is going from bad to worse the Government has been constantly requested by Members of Parliament to order a

CBI inquiry into all fissy project contracts. What is the hitch for the Government to order an inquiry?

Is the Government aware that recently the Managing Director of the FCI spent as much as Rs. 5 lakhs on his daughter's marriage and the entire sets of utensils presented were of all pure gold? Is it also a fact that the entire top brass of FCI attended the wedding on official tours and in order to facilitate their attendance at the marriage, a number of meetings were fixed at Calcutta on that date?

**श्री देवकान्त बरुआ :** माननीय सदस्य ने जैसा कहा है, मेरे पास भी कागजात आये हैं और मैंने इस की जांच करने के लिये भी कह दिया है । कोई प्राइमा-फेसी केस बन जाय त. सी० बी० आई० को दिया जायेगा । इन्हीं कागजात में 20 लाख रुपये की शिकायत भी थी, जिस की जांच कराने के बाद वह सत्य प्रमाणित हुई ।

**श्री भोगेन्द्र झा :** यह प्राइमा-फेसी केस कब इस्टेब्लिश होगा ?

**श्री देवकान्त बरुआ :** मेरे कहने में गलती हुई है ——जब सन्देह होता है तब सी० बी० आई० को देते हैं । प्राइमा फेसी कैसे सी० बी० आई० बनायेगी । मेरे कहने में थोड़ी गलती हुई है, मेरी हिन्दी में थोड़ी दुर्बलता है । .....(व्यवधान) .....इस के बारे में अभी तीन-चार रोज हुए मेम्बर पार्लियामेन्ट ने लिख कर मुझे दिया है और मैंने तुरन्त कार्यवाही शुरू कर दी है । पहले डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी होगी, उस के बाद मामला सी० बी० आई० को जायेगा ।

**श्री रामावतार शास्त्री :** फार्टिलाइजर कारपोरेशन आफ़ इंडिया ने जितने लोगों को खाद बेचने के लिये लाइसेंस दिये हैं, उन में कितने निजी व्यापारी हैं और कितने अनएम्प्लाएड ग्रेजुएटस हैं——इन दोनों की संख्या बतलाइये ?

**श्री देवकान्त बरुआ :** शास्त्री जी ने पूछा है, मैंने उस की भी जांच कराने के लिये दिया है, क्योंकि इस के साथ उस का भी सम्बन्ध हैं ।

**श्री दामोदर पांडे :** मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्हें कोआपरेटिव मार्केटिंग की मारफत फर्टिलाइजर बेचने में क्या परेशानी है, लेकिन बजाय उन के आप प्राइवेट ट्रेडर्स को मार्केटिंग के लिये दे देते हैं जिस में बंगलिंग हो जाती है ? दूसरी बात-यह मामला 1971 से आप की मिनिस्ट्री की नोटिस में लाया जा रहा हैं, क्या वजह है कि तमाम जानकारी होने के बावजूद जो बंगलिंग चल रहा है, उस को रोका नहीं गया ?

**श्री देवकान्त बरुआ :** महाशय जी, हमारे माननीय सदस्य पांडे जी ने पूछा है कि मंत्री महोदय को क्या परेशनी है कि वे प्राइवेट को देते हैं, कोआपरेटिव को नहीं देते हैं——मंत्री महोदय को भी यही परेशानी है कि कोआपरेटिव को क्यों नहीं दिया जाता है । मैं इस की चेष्टा कर रहा हूं, कृषि मंत्री जी के साथ भी इस बारे में बात-चीत कर रहा हूं, क्योंकि इस काम की ज़िम्मेदारी कृषि विभाग को लेना चाहिये । एफ० सी० आई० का काम तो उत्पादन में वृद्धि होना चाहिये, व्यापार में लिप्त होना मैं उन के लिये उचित नहीं समझता हूं ।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** अध्यक्ष जी, पहले सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों को छुट्टी पर जाने दिया है । छुट्टी पर जाने दिया है, इस का अर्थ यह है कि उन को लीव पर जाने दिया है । उन्हें सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया, उन्हें लीव पर क्यों जाने दिया गया ?

**श्री देवकान्त बरुआ :** जब सी० बी आई० की रिपोर्ट आजायगी और ऐसा मालूम होगा कि इन लोगों के दोषी

होने की सम्भावना है, तब पनिश किया जायेगा या सस्पेंशन में डाला जायेगा । सी० बी० आई० को कहा गया है कि वे अपनी रिपोर्ट जल्दी दे दें कि किन-किन आफिसर्ज पर वे सन्देह करते हैं । हम ने उन्हें छुट्टी पर इस लिये जाने दिया कि वे सीनियर आदमी थे, जिम्मेदार आदमी थे, उनकी जानकारी में यह काम हुआ है । जब सी० बी० आई० की रिपोर्ट आ जायेगी तब उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

**Expansion of Trombay Fertilizer Project**

*308. SHRI BIRENDER SINGH RAO:
SHRI M. V. KRISHNAPPA:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether the proposed expansion of the Trombay Fertilizer project has since been considered by Government; and

(b) if so, the nature of decision taken?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI D. K. BOROOAH): (a) and (b). A plan to expand the Trombay project is under consideration of Government. Different Schemes have been suggested in this connection and these are being appraised. No decision has yet been taken.

SHRI BIRENDER SINGH RAO: I would like to know from the hon Minister as to what the total cost involved is in this proposed expansion programme. Secondly, what is the total installed capacity for the production of the plant? What is the actual outturn of the plant during the current year? And if there is a big gap between the total installed capacity and the actual production what are he reasons for it?

SHRI D. K. BOROOAH: Sir, there have been many schemes. The total cost of the schemes which have been accepted ultimately is Rs. 37.5 crores with a foreign exchange compoment of Rs. 13.8 crores. The revised project has been approved by the Board and submitted to the government. The report has also been submitted to the World Bank. The project would be completed in about 30 months starting from June, 1973. I do not have the detailed information but the Trombay project production capacity forms a substantial part.

---

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

**Irrigation in Chambal area**

*309. SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether despite heavy investment on the Chambal Project, the pace of irrigation in the area has been slow; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

*Statement*

(a) and (b). The Chambal Project had been planned for annual irrigation of 2.83 lakh ha. each in Rajasthan and Madhya Pradesh, with an intensity of 76 per cent over culturable command area in Rajasthan and 61 per cent in Madhya Pradesh.

The Government of Rajasthan have reported that the canals constructed by them can serve a net culturable commanded area of 2.29 lakh ha. and that 1.74 lakh ha. of annual irrigation is being done at present. This is about 61 per cent of that originally envisaged.

The potential created in Madhya Pradesh is about 2.62 lakh ha. The maximum irrigation done so far has been about 1.29 lakh ha. or about 45 per cent of that originally envisaged.